



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264426
CG-DL-E-07072025-264426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2946]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2025 /आषाढ़ 13, 1947

No. 2946]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2025 /ASHADHA 13, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2025

का.आ. 3013 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वीप समूह संरक्षण जोन (आईपीजेड) अधिसूचना, 2011 कहा गया है) द्वारा मध्य अंदमान, उत्तरी अंदमान, दक्षिणी अंदमान और बृहद निकोबार के कतिपय समुद्रीय क्षेत्रों तथा अंदमान और निकोबार और लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूहों के संपूर्ण क्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय जल सीमा तक उनके जल क्षेत्र को द्वीप समूह संरक्षण जोन घोषित किया था और उक्त जोन में उद्योगों, प्रचालनों और प्रसंस्करणों की स्थापना करने और उनका वर्धन करने पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे ;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 कहा गया है) द्वारा निदेश दिया कि नई परियोजनाएं या क्रियाकलापो या विस्तार या विद्यमान परियोजनाओं का आधुनिकीकरण या ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध गतिविधियां, जिनमें प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी या उत्पाद में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि

शामिल है, यथास्थिति, भारत के किसी भी भाग में केन्द्रीय सरकार या राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही शुरू की जाएंगी;

और आईपीजेड अधिसूचना, 2011 के अधीन अनुदत्त मंजूरी नई परियोजनाएं या क्रियाकलाप या विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण को भी लागू है, जो अधिसूचना के अधीन प्रस्तावित हैं तथा ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में भी सूचीबद्ध हैं, जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी अनुदत्त की जाती है ;

और, आईपीजेड अधिसूचना, 2011 में मंजूरी की वैधता से संबंधित कतिपय उपबंध ईआईए अधिसूचना, 2006, और उसमें संशोधन के अनुरूप नहीं है तथा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आईपीजेड अधिसूचना, 2011 को यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के समरूप बनाने के लिए इसका संशोधन करना आवश्यक है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) उपबंध करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह उक्त नियमों के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से छूट दे सकती है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिसूचना को जारी करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से छूट लोकहित में है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 20(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 के मद घ में, -

(i) उपमद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8. इस अधिसूचना के अधीन परियोजनाओं को दी गई मंजूरी दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी :

परंतु द्वीप समूह संरक्षण जोन मंजूरी की वैधता की अवधि एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी, यदि संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के साथ मंजूरी की वैधता की अवधि के भीतर आवेदक द्वारा आवेदन किया जाता है :

परंतु यह और कि जहां इस अधिसूचना के अधीन मंजूरी की वैधता की अवधि के विस्तार के लिए आवेदक द्वारा आवेदन, -

(क) ऐसी वैधता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के भीतर फाइल किया जाता है तो विलंब को यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संबंधित प्रभाग के प्रमुख या तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य-सचिव द्वारा क्षमा किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात् आवेदन को मंजूरी की वैधता की अवधि के विस्तार के लिए विचार हेतु समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ख) ऐसी वैधता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किंतु 90 दिन के भीतर फाइल किया जाता है तो विलंब को यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारसाधक मंत्री या तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष

द्वारा क्षमा किया जा सकेगा तथा तत्पश्चात् आवेदन को मंजूरी की वैधता की अवधि के विस्तार के लिए विचार हेतु समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु यह भी कि आईपीजेड मंजूरी की वैधता की अवधि की समाप्ति के 90 दिन के परे विस्तार के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपमद के प्रयोजन के लिए, “मंजूरी की वैधता” से वह अवधि अभिप्रेत है, जिससे आवेदक को परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन का आरंभ करने के लिए आईपीजेड मंजूरी दी जाती है या संनिर्माण परियोजनाओं के मामले में सभी संनिर्माण परियोजनाओं के पूर्ण होने की अवधि अभिप्रेत है, जिससे आईपीजेड मंजूरी के लिए आवेदन निर्दिष्ट है ।

8क. परियोजना, जिसमें पर्यावरण मंजूरी तथा आईपीजेड मंजूरी, दोनों अपेक्षित हैं, ऐसी मंजूरीयों की वैधता समय-समय पर यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना के अनुसार होगी :

परंतु ऐसी मंजूरी की वैधता की अवधि का विस्तार संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण तथा संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा ।

8ख. उपमद 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि कोरोना वायरस (कोविड-19) फैलने को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिसूचना के अधीन अनुदत्त मंजूरी की वैधता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं ली जाएगी ।”;

(ii) उपमद 10 के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“11. किसी आवेदक को विनिर्दिष्ट परियोजना या क्रियाकलाप के लिए दी गई आईपीजेड मंजूरी उसकी वैधता के दौरान उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जिनके अधीन आरंभ में आईपीजेड मंजूरी दी गई थी और मंजूरी की वैधता की उसी अवधि के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा, अंतरक द्वारा लिखित में अनापत्ति के साथ, अंतरक द्वारा या अंतरिती द्वारा आवेदन करने पर उस परियोजना या क्रियाकलाप करने के हकदार किसी अन्य विधिक व्यक्ति को अंतरित की जा सकेगी ।

12. विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए दी गई आईपीजेड मंजूरी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अंतरक द्वारा किए गए आवेदन पर इसकी वैधता के दौरान किसी अन्य विधिक व्यक्ति को अंतरित मंजूरी, परियोजना करने के हकदार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विभाजित की जा सकेगी तथा केंद्रीय सरकार या संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण, मंजूरी को संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् तथा यदि अपेक्षित हो तो संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्, संबंधित परियोजनाओं के लिए अन्य विधिक व्यक्तियों को मंजूरी विभाजित और अंतरित कर सकेगी ।

13. उपमद 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पर्यावरण मंजूरी और आईपीजेड मंजूरी, दोनों की अपेक्षा वाली परियोजनाओं के लिए मंजूरी का अंतरण संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात् समय-समय पर यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार होगा ।”।

[फा.सं. 19-112/2013-आईए.III(पार्ट-3)]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित की गई :-

1. का .आ.3840(अ), तारीख 3 अगस्त, 2018
2. का .आ.2090(अ), तारीख 5 मई, 2022

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2025

S.O. 3013(E).— WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O.20 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Islands Protection Zone (IPZ) Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches of the Middle Andaman, North Andaman, South Andaman and Greater Nicobar and entire area of the other islands of the Andaman and Nicobar and the Lakshadweep and their water area upto territorial water limit as the Islands Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

AND WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the Environment Impact Assessment Notification, 2006), the Central Government directed that new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the Environment Impact Assessment Notification entailing capacity addition with change in process or technology or product shall be undertaken in any part of India only after obtaining prior Environmental Clearance from the Central Government or by the State Level Environment Impact Assessment Authority, as the case may be;

AND WHEREAS, the clearance granted under IPZ Notification, 2011 are also applicable to the new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities which are proposed in the Notification, and are also listed in the Schedule to the EIA Notification, for which Environmental Clearance is granted;

AND WHEREAS, certain provision related to validity of clearance in the IPZ Notification, 2011 and its amendment therein is not in conformity with EIA Notification 2006 and the Central Government is of the opinion that it is imperative to amend the IPZ Notification, 2011 to make it in consonance with EIA Notification 2006 as amended;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest so to do, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub- rule (3) of the said rules;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub –rule (3) of rule 5 of the said rules to issue this notification;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby, makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011, namely:-

In the said notification, in paragraph III, in item D,—

(i) for sub item 8 and the entire relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“ 8 The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for a period of ten years:

Provided that the period of validity of the Islands Protection Zone clearance may be extended by a maximum period of one year, if an application is made by the applicant within the period of validity of the clearance along with the recommendations of the Coastal Zone Management Authority concerned:

Provided further that where the application for extension of period of validity of clearance under this notification is filed by the applicant,-

(a) within thirty days after expiry of the period of such validity, the delay may be condoned by the head of the division concerned in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Member-Secretary of the Coastal Zone Management Authority, as the case may be, and thereafter the application shall be referred to the appropriate authority for consideration of the application for extension of period of validity of the clearance;

(b) thirty days after expiry of the period of such validity but within ninety days after expiry of such validity, the delay may be condoned by the Minister in charge of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Chairperson of the Coastal Zone Management Authority, as the case may be; and thereafter the application shall be referred to the appropriate authority for consideration of the application for extension of period of validity of the clearance:

Provided also that no application for extension filed beyond ninety days after the expiry of the period of validity of IPZ clearance shall be entertained.

Explanation.- For the purpose of this sub-item, the “validity of clearance” means the period from which IPZ clearance is granted to the applicant, to the start of production operations by the project or activity; or the completion of all construction operations in case of construction projects, to which the application for IPZ clearance refers to.

8 (a) The project which requires both the environmental clearance and IPZ clearance, the validity of such clearances shall be in accordance with the EIA Notification, as amended from time to time:

Provided that the extension of period of validity of such clearance shall be after obtaining recommendation from the Coastal Zone Management Authority concerned and the Expert Appraisal Committee concerned.

8 (b) Notwithstanding anything contained in sub-item 8, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of clearance granted under this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19).”;

(ii) after sub-item 10, the following sub-items shall be inserted, namely:-

“11. An IPZ clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written no objection by the transferor, to, and by the authority concerned, on the same terms and conditions under which the IPZ clearance was initially granted, and for the same period of validity of the clearance.

12. An IPZ clearance granted for a specific project, may be split amongst two or more legal persons, entitled to undertake the project and transferred during the validity to another legal person on application made by the transferor along with requisite documents and the Central Government or the Coastal Zone Management Authority concerned shall split and transfer the clearance to the other legal persons for the

respective projects, after obtaining recommendation by the Coastal Zone Management Authority concerned and if required the recommendation of the Expert Appraisal Committee concerned.

13. Notwithstanding anything contained in sub-item 12, the projects requiring both Environmental Clearance and IPZ clearance, the transfer of clearance shall be in accordance with the provisions of the EIA Notification, as amended from time to time, after obtaining recommendation of the concerned CZMA”.

[F. No. 19-112/2013-IA.III(Part-3)]

VED PRAKASH MISHRA, Jt Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 20 (E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 3840(E) dated the 3rd August, 2018
2. S.O. 2090(E) dated the 5th May, 2022